RAJYA SABHA

Friday, the 27th February, 1987/8th Phalguna, 1908 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 41—Hon. Member absent.

Question No. 42—Hon. Member absent.

Question No. 43.

*41. [*The questioner (Shri N. E. Balaram was absent. For answer,* vide *col.* 29-30 infra].

*42. [*The questioner (Shrimati Krishna Kaul) was absent. For answer,* vide *col.* 30 infra].

Rising prices of edible oils

*43. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the rising prices of edible oils; and

(b) if so, what steps Government propose to take to control the price level?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) The steps taken by the Government to control the prices are as under:—

(i) States have been asked to take stringent measures against hoarders and speculators. Checking of vanaspati units has been intensified.

(ii) All efforts are being made to increase the production of edible oils to achieve self-sufficiency.

(iii) Supply management of imported edible oils to Public Distribution System and vanaspati industry has been geared to check the rising trend in the prices.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, खाद्य तेलों के बढ़ते मूल्यों से आम व्यक्ति पीड़ित है । गत एक वर्ष में खाद्य तेलों का मूल्य सूचकांक 299.6 से 408.2 तक बढ़ा है । इक्कीसवीं शताब्दी में जाने की जल्दी में शायद तेल के दाम 20 रुपया किलो से नीचे आने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या तेलों में वृद्धि के कारण आयात और निर्यात व्यापार में बढ़ते हुये घाटे को कम करने की दृष्टि से तेलों के आयात में भारी कटौती की गयी है और उसका कारण यह है कि तेलों के दाम बढ़े हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत वर्ष हमने कितना तेल आयात किया और इस वर्ष कितना आयात किया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें जो फर्क पड़ा है उसी के कारण तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय यह तो सत्य बात है कि खाने के तेलों के दाम बढ़े हैं । फिर भी फरवरी में पिछले पांच महीने के मुकाबले में जरा कम हुआ । लेकिन पहले 6 महीने या पिछले साल जो दाम थे उसके मुकाबले दाम काफी बढ़े हैं । इसका कारण यह रहा है कि जो नयी एडिबिल आयल की पालिसी है उसमें एक बात तो यह है कि अगर हमें तेलों के मामले में अपने पैरों पर खड़े होना है तो हमें किसी हद तक जो एडिबिल आयल सीड के ग्रोवर्स हैं उनको इनकरेज करना पड़ेगा ताकि उनको ठीक दाम मिल सकें और साथ ही साथ कंज्यूमर्स पर भी ज्यादा बोझ न पड़े इस बात की भी कोशिश करनी है । तीसरी बात जो है यह बात सत्य नहीं है कि सिर्फ क्योंकि फारेन एक्सचेंज का हम पर ज्यादा बोझ हो गया है इसके कारण तेलों के दाम बढ़ाये गये हैं । हमारी तेल की जो पालिसी है उसमें तीन फैक्टर्स हैं उनको रीकंसाइल करने की कोशिश की गयी है । इंडीनिजस, आयल वालों को ठीक दाम मिले और कंज्यूमर्स पर बहुत ज्यादा बोझा न पड़े, इसका ध्यान रखा गया है । इसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है वह कम रखा जाए ऐसी कोशिश है । जो इम्पोर्ट पिछले साल किया गया था, इस समय उससे कुछ कम टारगेट रखा गया है इसलिये शुरू में

वनस्पति को तेल कुछ कम दी गई । पी० डी० एस० सिस्टम वही रखा गया है लेकिन बाद में उसको कुछ बढ़ाया है और गवर्नमेंट सिचुयेशन पर वाच रखे हुये हैं तथा दाम बहुत ज्यादा न बढ़ जायें इस बात की पूरी कोशिश है, इस पर पूरी नजर रखी हुई है । पिछली जनवरी के मुकाबले फरवरी के मुकाबले में इम्पोर्टेड तेलों को वनस्पति को अधिक देने से, दामों में किसी हद तक कमी आयी है ।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, आत्मनिर्भरता के प्रयासों का तो हर व्यक्ति स्वागत करेगा । हमारे देश में तेल की आवश्यकता हर वर्ष चार प्रतिशत से बढ़ती है और उत्पादन दो प्रतिशत से बढ़ता है । इसलिये स्वतंत्रता के पूर्व तेलों का निर्यात करने वाला यह देश आज तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है और इसीलिय इस आत्मनिर्भरता की नीति को लेकर मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी लागत के आधार पर वास्तविक मूल्य देकर और उनको प्रोत्साहन देकर तिलहन का अधिक उत्पादन करने का प्रयास सरकार करेगी ? और इस दृष्टि से गत वर्ष हमने तिलहनों को क्या भाव दिया था और तेल का क्या भाव था । इस वर्ष हमने तिलहनों को क्या भाव दिया और तेल का भाव क्या दिया, इसका कोई कम्पैरीजन सरकार करके बताये ।

श्री एच० के० एल० भगत : यह बात सत्य है, सरकार कोशिश करेगी, कर रही है कि हमारे भारत में तिलहन ज्यादा बढ़े । इसके बारे में कुछ मेजर्स लिये गये हैं वे मैं अभी बताता हूं । दूसरी बात यह है कि जहां तक इसका ताल्लुक है हमारे तेलों के दामों का, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं इसलिये किसी हद तक कुछ न कुछ बोझा कंज्यूमर्स पर ज्यादा पड़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और दाम बढ़ रहे हैं कुछ आयल सीड्स के, वैसे तो कंट्रोल नहीं है आयल सीडस पर या जो इंडिजेनस आयल है उस पर कंट्रोल नहीं रखा गया है लेकिन आयल सीड्स को कुछ बढ़ाने के लिये इस दफा सरक र ने दाम कुछ बढ़ाये हैं । यह जो साल है इसमें पहले से बेहतर हुआ है लेकिन जितनी आशा थी नहीं हुआ है । आज भी जो गैप है वह करीब 15 लाख टन का गैप है हमारी रिक्वायरमेंट से हमारा जो प्रोडक्शन है उससे । लेकिन तिलहन को जो हमारे देशी तेल हैं इनको बढ़ानें के लिये गवर्नमेंट ने कई कदम इनके बारे में तय किये हैं एक नेशनल आयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है, नेशनल डेरी डेवलपमैंट बोर्ड का आयल सीड्स प्रोजेक्ट है और बेटर इंसेंटिव बाई फिक्सेशन आफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ जरा सा किया गया है । इसकी कितनी प्राइस तय की गयी है, इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

Then intensification of research efforts for increasing the productivity of oilseeds; increase in area under non-traditional oilseed crops like soyabean, sun-flower, etc.; exploitation of oilseeds of tree and forest origin, ricebran, etc.; setting up necessary processing infrastructure facilities to keep pace with the production programme of oilseeds; setting up a technological mission for oilseeds production under the orders of the Prime Minister.

ये कई स्टेप्स हैं जो देशी तेलों को बढ़ाने के लिये किये जा रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जो उन्होंने पहले आइटम में लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिये जाने के लिये उहोंने आदेश भेजे हैं तो गत 6 महीने से जो प्राइसेज इनकी बढ़ती चली जा रही है क्या उनके पास ऐसे कोई फिगर्स हैं ? वे यह बतायें कि क्या-क्या स्ट्रिंजेट मेजर्स इस बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने लिये हैं टु कन्ट्रोल होर्डिग, टु चेक आयल प्राइसेज ? जो दूसरा उन्होंने कहा कि हम एफर्टस कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये लेकिन उपभोक्ता को भी भार ज्यादा न पड़े । आपकी जो फारेन एक्सचेंज है जो बहुत कम है देश में उस पर भार न पड़े क्योंकि 14 सौ करोड़ खर्च करके बाहर से मंगाते हैं । आपने उत्तर दिया कि मेरे पास कितने प्राइसेज बढ़े हैं इसकी फिगर्स नहीं हैं । जब तक लाभप्रद प्राइस किसानों को नहीं मिलेगा, न एरिया बढ़ेगा और न किसान अधिक पैदा कर

सकेंगे । मान्यवर, जो तीसरी बात आपने कही है, क्या यह सही है कि जितना आपने इम्पोर्टेड आयल को अधिक डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे फिगर्स मेरे पास हैं, कि उसी समय प्राइसेज अधिक बढ़े हैं, उससे प्राइस कंट्रोल नहीं हुआ है ।

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा नहीं है, मैंने यह नहीं कहा है कि कितने दाम बढ़े हैं उसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं आयल की । मेरे पास तो आयल के होलसेस के दाम कितने बढ़े हैं . . . (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : किसानों के ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उसके बारे में कह रहा हूं । जो एडीबुल आयल के दाम हैं होलसेस में रिटेल में कितने बढ़े हैं, किस तरह से बढ़े हैं वह ब्यौरा मेरे पास है, आनरेबुल मेम्बर चाहेंगे तो मैं दे दूंगा । दूसरा उनका कहना है कि हमने राज्य सरकारों को कहा । तो उन्होंने इस सिलसिले में रेड वगैरह किये । मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा और सबने उसका जवाब दिया कि हमने कुछ डीहोर्डिंग आपरेशन किये हैं कुछ हमने रेड किये हैं, कुछ फ्लो ज्यादा हुआ है, कुछ फलश सीजन में थोड़ा रुका था कुछ आना शुरू हुआ है । लेकिन बुनियादी तौर पर तेलों की कमी है, इंडिजेनस आयल के प्रोड़क्शन की, डिमांड ज्यादा है उस सूरत में कुछ नेचुरल फैक्टर हैं कई जगह जितना हम चाहते थे बढ़ेगा, जो इस्टीमेट थे पूरे नहीं हुये, कई जगह ड्राऊट वगैरह हुए लेकिन उन्होंने डिहोर्डिंग आपरेशन वगैरह किसी हद तक कुछ स्टेट्स ने किये हैं और हमको खबर भी दी है । तो हमारी कोशिश यह है । यह जो तेल के दाम बढ़े हैं, उसमें शुरू-शुरू में जब आयल सीड्ज किसान के पास होते हैं तो उसको किसी हद तक ज्यादा दाम मिलता है । हम चाहते हैं कि दाम ज्यादा मिलें । बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, जिसका बोझा कंज्यूमर पर भी पड़ता है, किसी हद तक किसान पर भी और हम चाहते हैं कि किसी हद तक फोरेन एक्सचेंज के खर्च में भी कमी हो । तो इन सारी चीजों को मिला कर के पालिसी बनाई गई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : *

MR. CHAIRMAN: Do not record.

SHRI M. KADHARSHA: Sir, the price of edible oils has increased from 40 to 70 per cent as compared to last year. The price of groundnut oil which was only Rs. 1500 per quintal last year has shot up to Rs. 2,050 this year. Similarly, the gingelly oil has shotup from . . .

MR. CHAIRMAN: Questions should be short.

SHRI M. KADHARSHA: . . Rs. 1200 to Rs. 2400 at present. Then the production of oilseeds remains the same whereas the consumption is increasing by 12 per cent annually. So, I would like to know from the hon. Minister if there is any policy evolved by the Government to produce more oilseeds, will it be possible to produce more edible oil and what steps is the Government taking to secure the maximum output of oil from oilseeds.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, I have already detailed a number of steps—not one, but a number of steps—which the Government has taken for more or increased production of oilseeds. I have also already said that the prices of oils including those of groundnut oil have certainly gone up. But during the last month, comparatively, marginally I would say, when we decided to give a little more **oil from February onwards to vanaspati**, there has been some decline. As compared to January the position is slightly improved in February. I have already said that a number of steps have been taken by the Government to increase oilseeds production.

MR. CHAIRMAN: You have not answered one point. Is there any attempt being made to extract more oil from the same quantity of oilseeds?

*Not recorded.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, so far as this question is concerned, the prices of oilseeds have increased in proportion...

MR. CHAIRMAN: No, no. The point is this. Please hear me first. The point raised by the Hon. Member is whether there is any attempt made to increase the productivity of oil from a given quantity of oilseeds. Suppose there is an 'X' quantity of oilseeds. What is the amount of oil that can be extracted from it now and can it be increased?

AN HON. MEMBER: Even now, he has not understood.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Gopalsamy.

SHRI H. K. L. BHAGAT: Sir, I have followed the question. I am grateful to you. Sir, I am grateful to you for clearing the question to me. I had not understood it first. Now, the question is whether from a certain quantity of oilseeds, by an improvement in extraction technology, we can get more oil from the same quantity of oilseeds. That is again a matter for which some kind of a technological mission has been set up so that we can improve the production from oilseeds through improved technology.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Chairman Sir, the high price rise of all edible oils has put a heavy burden on the consumers. I would like to know from the Hon. Minister for what reasons the Government chose to restrict edible oil imports at a time when availability from indigenous sources has been affected by a drop in the yield. I would also like to know from the Hon. Minister whether efforts would be made to secure maximum output of oil with the processing of cotton seed and rice bran and a steady increase in the yield of soyabean and other rabi crops along with adequate imports.

SHRI H. K. L. BHAGAT: As I have already stated, steps that are being taken are not only to increase production of one category of oil but all categories, including soyabean oil. Secondly, with regard to increase in prices, one way is—and probably the only way is—that we release more oil through public distribution system. A number of steps are being taken and we are keeping a watch on the situation so that whatever possible we can do to keep prices in check, we should be able to do.

SHRI LAKSHMI KANT JHA: One thing which stands out from the question and the answer is that the prices of vegetable oil were raised but they did not benefit the farmer; they benefited the traders in between. Would it not be better from the future point of view to have the emphasis on giving a better yield to the farmer, determining what should be the price level of oil commensurate with that and ensuring that the import instrument is used to maintain price at that level and no higher, so that there is justice to the consumer and the producer? May I ask whether he would consider giving direct price support to some of the unconventional oilseeds which have a very high yield not only in terms of oil per tonne of seed but also in terms of total yield, such as sunflower, which is a neglected oilseed. It can grow here and it does grow here. If you give price support to them, would it not give us a much better contribution? But it needs direct intervention in the market and not hoping that oil price increase would automatically give necessary stimulus to production.

SHRI H.K.L. BHAGAT: It is a very relevant suggestion that increase in oil price should benefit the grower, particularly when seeds come up for sale point. I am in agreement with him. It is Ministry of Agriculture which deals with the subject and I will convey it to the Ministry concerned. I quite agree with this.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मेरे ख्याल से सरकार से एक गलती यह हुई कि फसल आने के आठ महीने पहले ही उसने इम्पोर्ट को बंद किया और उसकी घोषणा कर दी। अगर फसल आने के वक्त में सरकार करती, तो एडिबल आयल और खाद्य तेल का इतना दाम नहीं बढ़ता।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पहला तो यही प्रश्न पूछूंगा कि इतना पहले इसको क्यों किया गया जिससे

प्राफिटियर्ज लोगों ने इससे फायदा उठाया ?

दूसरा यह है कि जो इस बीच में प्राफिटियर्ज ने फायदा उठाया--सरकार का लक्ष्य था कि किसानों को पैसा मिले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई मेकैनिज्म है जिससे हम लोग जान सकें कि इस बीच में जो अतिरिक्त मूल्य बढ़े, उसमें कितना किसानों को मिला और कितना मुनाफाखोरों को मिला और अगर ऐसा नहीं है, तो क्या सरकार ऐसा मेकैनिज्म बनायेगी ?

इन्हीं चंद बिन्दुओं पर मैं सफाई चाहता हूं ।

SHRI H.K.L. BHAGAT: The question which the hon. Member has raised is very important and very relevant. But it is not correct that the Government decided to reduce the imports at an incorrect time. As I said, some mechanism is to be evolved to see for example at what stage more imported oil should be given. It should be at a time when there is a leas season, and not when oil seeds are available in the market. Nothing should be done to harm the interest of the grower. The mechanism which the hon. Member has suggested will be looked into.

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 44. Dr. Govind Das Richariya. Next question.

AN HON. MEMBER: Sir, Dr. Rachhariya is here.

MR. CHAIRMAN: He may be here, but he did not get up. Therefore, he has lost his chance.

*44. [*The questioner (Dr. Govind Das Kumar Bansal) was absent. For answer,* vide *col.* 30-31 infra].

*45. [*The questioner (Shri Pawan Kumar Bansal was absent. For answer* vide *col.* cv, infra].

*46. [*The questioner (Shri Rasheed Masood and Shri Ram Naresh Kushawha) were absent. For answer,* vide *col.* 31 infra].

*47. [*Transferred to the 3rd March,* 1987].

Stoppage of supply of sugarcane by the growers

*48. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several sugar mills in the different parts of the country are facing a crisis due to stoppage of sugarcane supply to the mills by the cane growers;

(b) if so, what are the demands of the cane growers;

(c) whether the Central Government have taken any action in this regard and

(d) if not, by when the demands of the cane growers are likely to be examined thoroughly and decision taken thereon?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H.K.L. BHAGAT): (a) No, Sir, the sugar mills are not facing crisis due to stoppage of sugarcane. In fact, as on 15th February 1987, 329 sugar factories were working as against 313 factories in 1986 and 277 factories in 1985 on the same date.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The Central Government fixes only the statutory minimum prices of sugarcane payable by sugar factories which, in effect serve as floor prices. These prices have already been announced for 1986-87 and 1987-88. In actual practice, cane growers receive prices higher than the statutory minimum price and during the current sugar season the average cane price is around Rs. 25 per quintal on an all-India basis.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपा : सर, मंत्री महोदय ने जो कहा कि शुगर मिल्स में